विकसित मध्यप्रदेश की ऊर्जा क्रांति

सोलर केपिटल बनेगा मध्यप्रदेश

ऊर्जादाता बनेंगे मध्यप्रदेश के किसान : मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव

मध्यप्रदेश सोलर केपिटल बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सौर ऊर्जा को लेकर विजन को आगे बढ़ाते हुए डॉ. मोहन यादव सरकार मप्र के गांवों व शहरों में सौर ऊर्जा के माध्यम से उजियारा फैलाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। नगरपालिका, नगरपरिषद एवं नगर पंचायत को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का विजन है कि भारत के निवासी सोलर ऊर्जा से भी आय के स्रोत को जरिया बनाएं। पिछले दिनों मप्र में हजारों परिवारों को सोलर ऊर्जा से जोड़कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में मप्र सरकार की कई योजनाएं निरंतर कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय में बढ़ोत्तरी एवं आर्थिक विकास के लिये संकल्पित है। मध्यप्रदेश अब देश की सोलर केपिटल ऊर्जाधानी बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं। प्रदेश के रीवा, नीमच और ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा का सशक्त हस्ताक्षर बन रहे हैं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रदेश के लिए वरदान है। अब सरकार छोटे निवेशकों और किसान भाइयों को भी बिजली उत्पादन का अवसर मुहैया कराने जा रही है। हमारे अन्नदाता, ऊर्जादाता बनने के पथ पर अग्रसर हैं।

प्रदेश में सौर ऊर्जा से केवल घरों में ही रोशनी नहीं पहुँच रही, बल्कि किसानों के खेत भी महक रही हैं। 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' से छोटे निवेशकों के साथ किसानों को भी लाभ मिल रहा है। इस योजना से वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को निवेश एवं रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। निवेशकों के साथ सरकार ने 25 साल तक बिजली खरीदने का समझौता किया है। निवेशकों को नीतिगत प्रोत्साहन के साथ सस्ती ज़मीन और तय बिजली रेट मिल रहा है। 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' से किसानों को अत्यधिक फायदा है। योजना से किसानों को दिन में भी सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अन्नदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। किसानों को रात में बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता और दिन में 8 घंटे तक लगातार बिजली मिल रही है।

नवकरणीय ऊर्जा में भविष्य के लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ रहा मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयास से मध्यप्रदेश 'हार्ट ऑफ इंडिया' बना है। अब नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में रोल मॉडल बनकर प्रदेश 'लंग्स ऑफ इंडिया' बनने का विजन हासिल कर रहा है। मध्यप्रदेश केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को ही पूरा नहीं कर रहा, बल्कि पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता बढ़ा रहा है। प्रदेश सरकार सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि भविष्य पर भी ध्यान दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में 20 हजार मेगावाट से ज्यादा नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो। वर्ष 2030 तक प्रदेश की 50 प्रतिशत ऊर्जा नवकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की योजना है। इसके लिए ऊर्जा वितरण और संरक्षण में कुशलता पाने के लिए हमने स्मार्ट ग्रिड और माइक्रो ग्रिड तकनीकों पर भी काम शुरू किया गया है। सोलर पार्क, पवन ऊर्जा पार्क, फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना कृषि और व्यवसाय को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना

मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये महत्वपूर्ण सौगात दी है। आगामी समय में 32 लाख से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखकर कार्य किया जा रहा है। किसान अपनी आवश्यकतानुसार सौर ऊर्जा का उत्पादन कर खेती कार्य में उपयोग कर सकेंगे। किसान भाई सिर्फ बिजली का उत्पादन ही नहीं करेंगे, बल्कि सरकार को भी बिजली बेचेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संकल्प है कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाई जाए।

ओंकारेश्वर 600 मेगावाट की सबसे बड़ी सोलर परियोजना

ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले दशक की सबसे बड़ी चुनौती केवल बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि बिजली का भंडारण और मांग के अनुरूप उपलब्धता है। मध्यप्रदेश ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए ऐसी परियोजनाओं पर काम शुरू किया है जो उसे देश के अग्रणी ऊर्जा नवाचार केंद्रों में स्थापित कर रही हैं।

ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर विकसित हो रही 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में गिनी जा रही है। जलाशय की सतह पर स्थापित सौर पैनल न केवल भूमि की आवश्यकता कम करते हैं, बल्कि वाष्पीकरण भी घटाते हैं। परियोजना से उत्पन्न बिजली का लाभ प्रदेश के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रिड को भी मिलेगा। दूसरी ओर नीमच में देश का सबसे बड़ा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना दिन में उत्पादित सौर ऊर्जा को संग्रहित कर आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करने की क्षमता प्रदान करेगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा की विश्वसनीयता बढ़ेगी और ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर बनेगी। प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क और 1000 मेगावाट कम्पोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना को भी स्वीकृति मिल चुकी है। आगर और नीमच की 880 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं ने प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में नया आयाम जोड़ा है।

सांची बना प्रदेश का पहला सौर शहर

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सांची को मध्यप्रदेश का पहला सौर शहर बनाया गया है। यह परियोजना 'नेट ज़ीरो कार्बन सिद्धांत' पर आधारित है। अर्थात जितनी ऊर्जा का उपभोग होगा, उतनी ही हरित ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। यह पहल प्रदेश के साथ पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनी है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 'टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक' रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लागू की है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आकर्षक और अनुकूल अवसर प्रदान किए हैं। कुसुम-सी योजना में लगभग 18,000 मेगावाट क्षमता विकसित हुई है। जिनमें किसानों, एमएसएमई और निजी डेवलपर्स ने व्यापक भागीदारी की है। योजना में किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 100% फीडर सोलरीकरण का प्रावधान किया है। मध्यप्रदेश में पंप हाइड्रो परियोजनाओं और बॉयोफ्यूल परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया है। अब तक 14 हजार 850 मेगावाट क्षमता की पंप हाइड्रो परियोजनाओं पर काम किया गया है। इनमें से 8 हजार 450 मेगावाट परियोजनाओं का विकास हुआ है। कंप्रेस्ड बॉयोगैस (सीबीजी) और बॉयोमास पैलेट परियोजनाओं के लिए प्रतिदिन 6 हजार 500 टन से अधिक क्षमता की परियोजनाएँ क्रियान्वित हो रही हैं।

आंकड़ों से आगे, आम जन के साथ : मध्यप्रदेश में खुशहाली लाती राहत की बिजली...

ऊर्जा क्षेत्र की सफलता केवल मेगावाट में नहीं मापी जाती, कि इस बात से तय होती है कि उसका लाभ आम नागरिक तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। मध्यप्रदेश में किसानों घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे उपभोक्ताओं को केंद्र में रखकर महत्वपूर्ण पहल की गई है। वर्ष 2024-25 में लगभग 35 लाख किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिजली सब्सिडी प्रदान की गई है। इससे सिंचाई की लागत में कमी आई है और कृषि उत्पादन में स्थिरता मिली है। किसानों को मात्र 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंच को आसान बनाया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी राहतकारी कदम उठाए गए हैं। 150 यूनिट से कम बिजली उपयोग करने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को करीब 5,400 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। इससे मध्यम आय वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट संतुलित रखने में मदद मिली है। बिजली बिल बकाया उपभोक्ताओं के लिए चलाई गई समाधान योजना भी उल्लेखनीय है। योजना के पहले चरण में 11.88 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिला। इससे 632 करोड़ रुपये की मूल राशि जमा हुई तथा लगभग 276 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया। इस योजना के प्रभाव से ग्रामीण परिवारों में बच्चों की पढ़ाई, छोटे व्यवसायों का संचालन और महिलाओं की घरेलू उत्पादक गतिविधियों को भी ऊर्जा की उपलब्धता मिली है। भविष्य में स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल भुगतान और लक्षित सब्सिडी व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ता सेवाओं को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाए जाने की योजना पर काम किया है।

- किसान हितैषी नीति • घरेलू बजट को राहत
- बिजली पहुंच में विस्तार • डिजिटल सेवाओं का विस्तार
- ग्रामीण विकास को समर्थन • सस्ती और सुलभ बिजली ने लाखों परिवारों की आर्थिक मजबूती में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

मध्यप्रदेश ने ऊर्जा उपलब्धता के क्षेत्र में बनाई नई पहचान

ऊर्जा किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश ने पिछले वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए बिजली उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाया है। प्रदेश में वर्तमान विद्युत उपलब्ध क्षमता 24,108 मेगावाट से अधिक पहुंच चुकी है। जिससे मध्यप्रदेश प्रमुख विद्युत उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। आज मध्यप्रदेश के उद्योगों में 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उत्पादन, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिला है।

विद्युत आपूर्ति की स्थिरता ने निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप नए औद्योगिक निवेशों को गति मिली है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार ने राहतकारी कदम उठाए हैं। वहीं किसानों को बिजली पर दी जा रही हजारों करोड़ रुपये की सहायता से कृषि लागत कम कम हुई है। ऊर्जा वितरण तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधोसंरचना उन्नयन कार्य किया जा रहा है।

देश की हरित ऊर्जा राजधानी बनने की राह पर मध्यप्रदेश

सूरज की किरणों से समृद्धिः मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता का नया अध्याय

मध्यप्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 62 गीगावाट सौर क्षमता की संभावनाएं चिन्हित की गई हैं और 2030 तक कुल ऊर्जा खपत का 50 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2025 निवेश, नवाचार और पर्यावरणीय संतुलन को साथ लेकर चलने का प्रयास है। इसके तहत 2027 तक 10,000 मेगावाट तथा आगे चलकर 10 गीगावाट से अधिक हरित ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

आगर, नीमच, रीवा और ओंकारेश्वर जैसे क्षेत्र देश के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्र बन चुके हैं। रीवा सौर पार्क पहले ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। यहीं ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं का लाभ केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। निर्माण गतिविधियों, संचालन, रखरखाव और संबद्ध उद्योगों में हजारों रोजगार अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आधारित आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और निर्यात आधारित हरित उद्योगों के माध्यम से मध्यप्रदेश देश की हरित ऊर्जा राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है।

- नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2025 लागू
- 62 गीगावाट सौर क्षमता की संभावना
- 2030 तक कुल ऊर्जा खपत का 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य
- रीवा, आगर, नीमच और ओंकारेश्वर बने हरित ऊर्जा केंद्र
- देश की सबसे कम दरों पर सौर ऊर्जा उत्पादन का मॉडल
- ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर विशेष फोकस

D-19102/26